



भारत सरकार

Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

उपभोक्ता मामले विभाग

Department of Consumer Affairs

100 दिन की उपलब्धियां

100 days achievements



उपभोक्ताओं के अधिकारों के सुदृढीकरण हेतु नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

- शीघ्रता से कार्यकारी उपाय करने के लिए केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के लिए जुर्माना
- खराब उत्पाद उपलब्ध कराने अथवा सेवा में कमी के लिए उत्पाद दायित्व प्रावधान
- सरलीकृत अधिनिर्णयन प्रक्रिया जिसमें निवास-स्थान अथवा कार्य-स्थल से शिकायत दर्ज करना शामिल है।
- वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में मध्यस्थता
- ई0-कॉमर्स तथा प्रत्यक्ष बिक्री के लिए नियम



The new Consumer Protection Act, 2019 strengthens the rights of the consumers

- The Central Consumer Protection Authority to provide swift executive remedies
- Penalty to check misleading advertisements
- Product liability provision to deter delivering defective products or deficient services
- Simplified adjudication process including filing complaint from place of residence or work.
- Mediation as an alternative dispute resolution process
- Rules for e-Commerce & Direct selling



उपभोक्ता मामले विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां

कॉनफोनेट

- देश में उपभोक्ता मंचों के बेहतर कामकाज के लिए इन संस्थाओं को 'कॉनफोनेट' योजना के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर और स्टॉफ की व्यवस्था की गई।
- देश में उपभोक्ता मंचों के आधुनिकीकरण के लिए 415 उपभोक्ता मंचों के कंप्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर को बदलने के लिए खरीद का आदेश दे दिया गया है। प्रत्येक राज्य आयोग को तीन डेस्कटॉप (आल इन वन) , सात आई-7 पी.सी., एक 5 के.वी.ए. यू.पी.एस. और एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक जिला मंच को दो डेस्कटॉप (आल इन



वन), तीन आई- 7 पी.सी. , एक 3 के.वी.ए. यू.पी.एस. और एक मल्टीफंक्शन प्रिंटर दिए जाएंगे।

- नए हार्डवेयर की खरीद और इंस्टालेशन का काम 15 अक्टूबर, 2019 तक पूरा हो जाएगा।
- इससे उपभोक्ता मंच , 'कॉनफोनेट' योजनांतर्गत विकसित की गई आनलाइन केस निगरानी प्रणाली (ओ.सी.एम.एस.) का कारगर तरीके से उपयोग कर सकेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को वाद सूची, मामले की स्थिति, मामले का इतिहास , दैनिक आदेश , निर्णय आदि के बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी।



CONFONET

- For effective functioning of the consumer for a, computer hardware/software and technical manpower have been provided to the Consumer Fora under the scheme 'Computerisation and Computer Networking of Consumer Fora in the country (CONFONET).
- To modernise the Consumer Fora in the country, purchase order for replacement of computer hardware and software has been placed for 415 Consumer Fora. A State Commission will be provided with three Desktops(All in one), seven i7 PC, one 5KVA UPS and one multifunction printer. A District Forum will be provided with two desktops(All in one) three i7 PC, one 3KVA UPS and one multifunction printer.
- Procurement and installation of the new hardware will be completed by 15th October, 2019.
- This will enable the Consumer Fora to effectively use the Online Case Monitoring System(OCMS) developed under the CONFONET scheme, benefitting the consumers in getting information on cause list, case status, case history, daily order, judgement, etc.



स्टॉक सीमाओं से संविदा खेती के अंतर्गत क्रेताओं को छूट प्रदान करना

किसी राज्य द्वारा इस संबंध में बनाए गए एक्ट के तहत पंजीकृत किसी कृषि उत्पाद के खरीददार पर स्टॉक-सीमा , पंजीकृत मात्रा की कुल सीमा तक लागू

नहीं होगी। इससे :-



- कृषि क्षेत्र में निवेश और प्रौद्योगिकी में

बढ़ोत्तरी होगी,

- किसानों को सुनिश्चित आय

प्राप्त होगी,

- आपूर्ति श्रृंखला

कार्यकलापों-

भण्डारण, शीत-



भण्डारण और शीत श्रृंखला, परिवहन में निवेश में वृद्धि होगी।

Exempting purchasers under Contract Farming from stock limits

Stock limit shall not apply to a contract farming purchaser of any agricultural produce registered under any State Act made in this behalf, subject to the overall ceiling of registered quantity. This will lead to –



- Increased investment and technology flow in farming sector,
- Assured income to farmers,
- Increased investment in supply chain activities – warehousing, cold storage and cold chain, transportation.

दालों के 16 लाख मीट्रिक टन के नए बफर स्टॉक का सृजन

- 5 प्रमुख दालों के लगभग 16 लाख मीट्रिक टन के नए बफर स्टॉक का सृजन किया गया है।



- बफर, उचित मूल्यों पर पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करता है।

• व्यापारियों द्वारा की जाने वाली अनैतिक जमाखोरी को नियंत्रित करता है।

Creation of a 16 LMT new pulses buffer stock

- New buffer of about 16 LMT created consisting of 5 major



pulse varieties,

- Buffer ensures reasonability of prices and adequate availability,
- Discourages hoarding by unscrupulous traders

राष्ट्रीय परामर्शी बैठक

- राष्ट्रीय परामर्शी बैठक, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों इत्यादि के प्रभारी मंत्रियों के साथ खाद्य महंगाई के मुद्दों पर परामर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र है।
- पांचवीं राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को किया गया और इसकी अध्यक्षता माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी द्वारा की गई।



- राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में आगामी वर्ष में कार्यान्वित किए जाने हेतु, एक राष्ट्रीय योजना पर सहमति बनी और उसे स्वीकार किया गया।

100 days achievements of Department of Consumer Affairs

National Consultation Meeting

- National Consultation Meeting (NCM) is a national mechanism of consultation with States/UTs through their Ministers of States/UTs in-charge of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs etc, on the issue of food inflation.
- 5th NCM held on 3rd September, 2019 and was chaired by Hon'ble Minister(CA,F&PD)
- The NCM agreed and adopted a national plan to be implemented over next year.



उपभोक्ता मामले विभाग की 100 दिन की उपलब्धियां

- कार्ययोजना में व्यापक रूप से ऐसे क्षेत्रों को कवर किया गया जो –
 - i. आवश्यक खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता उचित कीमतों पर सुनिश्चित करेंगे,
 - ii. आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों में उपयुक्त परिवर्तनों का



प्रस्ताव करते हुए , विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना , जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों

की उपलब्धता में सुधार हो,

- iii. उपभोक्ता संरक्षण और सशक्तिकरण की संस्थानिक प्रणाली को मजबूत बनाना।



100 days achievements of Department of Consumer Affairs

- The action plan broadly covered areas that would
 - i. Ensure availability of essential food items at reasonable prices
 - ii. Promote investment, especially in agriculture sector by proposing suitable changes in provisions under Essential Commodities Act, thereby improve availability of agricultural goods
 - iii. Strengthening institutionalized system of consumer protection and empowerment.



भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आरंभ की गई राष्ट्रीय प्रयोगशाला निर्देशिका

- इसमें स्थापन तथा उत्पाद-वार जांच सुविधा के साथ 4000 से अधिक प्रयोगशालाओं का डाटा शामिल किया गया है,
- प्रयोगशालाओं का वर्गीकरण, आई.एस.ओ. 17025 प्रत्याभयन और बी.आई.एस., एफ.एस.एस.ए.आई., ई.आई.सी., ए.पी.ई.डी.ए., सी.पी.सी.बी. नामक विभिन्न विनियामकों द्वारा अनुमोदन के आधार पर किया गया है।



100 days achievements of Department of Consumer Affairs

National Laboratory Directory launched by BIS

- Containing data of more than 4000 laboratories with location and product-wise testing facility,
- Categorisation of labs is on the basis of ISO 17025 accreditation and approval by various regulators namely, BIS, FSSAI, EIC, APEDA, CPCB.

